*भारत से संबंधित अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी : 2015**

इस आलेख में भारत के बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं और दावों की प्रवृत्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जो वर्ष 2015[1] की तिमाहियों के अंतराल की स्थिति के अनुसार है। इस उद्देश्य से, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी को संकलित किया गया है और उसका इस्तेमाल किया गया है। वैश्विक परिदृश्य में देखें तो यह आलेख भारत के बैंकों के अन्य देशों में अंतरराष्ट्रीय दावों और देयताओं की मोटे तौर पर तसवीर पेश करता है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा संकलित अन्य वित्तीय सांख्यिकी के बीच इस अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) में बैंकिंग प्रणाली पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर का ख़ाका प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रवाहों के संबंध में मध्यस्थता करने की बैंकों की भूमिका, राष्ट्रीय विफलता के जोखिम (कंट्रीरिस्क) के प्रति राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर, चलननिधि एवं अंतरण संबंधी जोखिम शामिल हैं। आईबीएस में शामिल है स्थानगत बैंकिंग सांख्यिकी (एलबीएस) तथा समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (सीबीएस) यह आलेख एलबीएस का विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो अंतरराष्ट्रीय देयताओं और दावों पर आधारित है जिनमें लिखतों/कंपोनेंट के प्रकार, करेंसी, निवासी का राष्ट्र तथा प्रतिपक्ष का सेक्टर/लेनदेन कारने वाली यूनिट तथा रिपोर्टिंग बैंक की राष्ट्रीयता शामिल है। सीबीएस से संबंधित डाटा में अवशिष्ट परिपक्वता तथा उधारकर्ता के क्षेत्र के अनुसार अंतरराष्ट्रीय / विदेशी दावों को प्रस्तुत किया गया है। इससे संबंधित डाटा भारतीय रिज़र्व बैंक वेबसाइट पर 30 जून 2016 को जारी किए जा चुके हैं।

पृष्ठभूमि

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) वित्तीय सांख्यिकी से संबंधित विभिन्न प्रकार के डाटा संकलित करता रहा है (http://www.bis.org/statistics/about_sbanking_stats.htm) और उन्हें समय-समय पर आवश्यकता के अनुरूप प्रस्तुत करता रहा है। आईबीएस से संबंधित डाटा में अंतरराष्ट्रीय/विदेशी दावों तथा देयताओं की स्थिति अवशिष्ट परिपक्वता तथा उधारकर्ता के क्षेत्र के अनुसार प्रस्तुत की गई है, साथ ही तात्कालिक उधारकर्ता राष्ट्र का एक्सपोजर तथा अंततः जोखिम उठाने वाले राष्ट्र के प्रति दावों का पुनः आबंटन (अर्थात् जोखिम का अंतरण) एवं व्युत्पत्ती गारंटी में एक्सपोजर और ऋण संबंधी वचनबद्धता की स्थिति दी गई है।

सीजीएफएस चरण 2 तक विस्तार

वर्ष 2007-08 के विश्व वित्तीय संकट ने यह आवश्यक कर दिया कि वित्तीय स्थिरता के विश्लेषण के लिए और बेहतर डाटा की ज़रूरत है साथ ही डाटा का विस्तार यथासंभव बीआईएस अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी तक किया जाए। वर्ष 2010 में विश्व वित्तीय प्रणाली समिति (सीजीएफएस) ने सांख्यिकी डाटा के बारे में होने वाले अंतराल पर कार्य करने के लिए बीआईएस एवं उसके सदस्य केंद्रीय बैंकों का एक तदर्थ समूह स्थापित किया था। इसके सांख्यिकी मामलों पर कार्य कर रहे अन्य समूहों से संपर्क स्थापित करते हुए इसकी समीक्षा की और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी के बड़ी संख्या में डाटा को प्राथमिकता देते हुए उसे विस्तार प्रदान किया, विस्तारित रिपोर्टिंग से पड़ने वाले लागत प्रभाव के संबंध में रिपोर्टिंग बैंकों का सर्वेक्षण किया, और समिति द्वारा समीक्षा करने के लिए विशेष प्रस्ताव तैयार किए थे। यह विस्तार दो चरणों में लागू किया गया। पहले चरण में उन डाटा पर फोकस किया गया जिन्हें अधिकांश केंद्रीय बैंकों द्वारा पहले ही संकलित कर लिया गया था और इस प्रकार प्रत्येक वित्तीय संस्था द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। चरण 2 के विस्तार में ऐसे डाटा शामिल है जिनके लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग की जानी है।

आईबीएस रिपोर्टिंग में सीजीएफएस के विस्तार का उल्लेख अनुबंध - I में किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईबीएस के लिए सीजीएफएस चरण 2 के विस्तार को भारत के सभी बैंकों में दिसंबर 2015 के अंत से लागू कर दिया है और बीआईएस को स्थानिक एवं समेकित बैंकिंग सांख्यिकी की एक आसान सा अवलोकन अनुबंध - II में दिया गया है।

वर्ष 2015 के दौरान सभी देशों में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग गतिविधियां मंद हुई हैं

1. बीआईएस ने सीमा पार के जितने देशों की देयताओं और दावों की रिपोर्टिंग की है वह स्थानिक (लोकेशन)बैंकिंग सांख्यिकी (एलबीएस) पर आधारित है, जिसकी सकल स्थिति वर्ष 2015 की सभी तिमाहियों में ऋणात्मक वृद्धि रही है (सारणी 1)।

* सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, मुंबई के बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग द्वारा तैयार किया गया।

[1] इस विषय पर पिछले आलेख भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के विभिन्न अंकों में प्रकाशित हुए हैं। पिछला आईबीएस से संबंधित डाटा 2014 से संबंधित था जिसे जुलाई 2015 में प्रकाशित किया गया था। आईबीएस से संबंधित पद्धति और अवधारणा के मुद्दे अनुबंध के रूप सितंबर 2012 में प्रकाशित किए गए थे।

सारणी 1 : समस्त रिपोर्टिंग देशों की स्थानिक बैंकिंग सांख्यिकी पर आधारित सीमा-पार देयताएं और दावे

(बकाया राशि अमरीकी ट्रिलियन डालर में)

इस माह के अंत में	दावे		देयताएं	
मार्च 2009	29.14	(-17.8)	24.98	(-19.5)
जून 2009	29.86	(-13.4)	25.33	(-15.6)
सितंबर 2009	30.21	(-8.2)	25.48	(-10.9)
दिसंबर 2009	29.52	(-3.7)	24.99	(-5.3)
मार्च 2010	29.21	(0.2)	24.77	(-0.9)
जून 2010	28.45	(-4.7)	24.43	(-3.6)
सितंबर 2010	30.58	(1.2)	26.17	(2.7)
दिसंबर 2010	29.76	(0.8)	25.66	(2.7)
मार्च 2011	30.98	(6.1)	26.68	(7.7)
जून 2011	31.13	(9.4)	26.75	(9.5)
सितंबर 2011	31.20	(2.0)	27.08	(3.5)
दिसंबर 2011	29.80	(0.1)	25.88	(0.8)
मार्च 2012	30.22	(-2.4)	26.27	(-1.5)
जून 2012	29.11	(-6.5)	25.08	(-6.2)
सितंबर 2012	29.48	(-5.5)	25.35	(-6.4)
दिसंबर 2012	29.18	(-2.1)	25.11	(-3.0)
मार्च2013	28.68	(-5.1)	24.62	(-6.3)
जून 2013	28.34	(-2.6)	24.60	(-1.9)
सितंबर 2013	28.57	(-3.1)	24.57	(-3.1)
दिसंबर 2013	28.98	(-0.7)	25.93	(3.3)
मार्च 2014	29.61	(3.2)	26.40	(7.3)
जून 2014	29.94	(5.7)	26.65	(8.4)
सितंबर 2014	29.26	(2.4)	26.03	(5.9)
दिसंबर 2014	28.53	(-1.5)	25.44	(-1.9)
मार्च 2015	28.09	(-5.1)	25.00	(-5.3)
जून 2015	27.66	(-7.6)	24.45	(-8.3)
सितंबर 2015	27.38	(-6.4)	24.18	(-7.1)
दिसंबर 2015	26.43	(-7.4)	23.17	(-8.9)

टिप्पणी : 1. ये डाटा समस्त रिपोर्टिंग देशों द्वारा बीआईएस को स्थानिक बैंकिंग सांख्यिकी के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए हैं।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता हैं।

स्रोत : : http://stats.bis.org/bis-stats-tool/org.bis.stats.ui.StatsApplication/StatsApplication.html

भारत के बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं घटी हैं किंतु अंतरराष्ट्रीय दावों में वृद्धि हुई है (एलबीएस पर आधारित)

2. भारतीय रिज़र्व बैंक आईबीएस डाटा को भारत में एवं विदेश में कार्यरत बैंकों से तिमाही आधार पर एकत्र करता है। पिछली चार तिमाहियों में भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में कमी दर्ज की गई है (चार्ट 1)। जबकि दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय दावों में जून 2015 से वार्षिक वृद्धि में लगातार बढ़ोतरी हुई है (चार्ट 1)।

3. जहां भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं दिसंबर 2015 के अंत में 173,212 मिलियन अमरीकी डालर थीं, वहीं भारत में बैंकों के अंतरराष्ट्रीय दावे 76,047 मिलियन अमरीकी डालर थे। विश्व के समस्त रिपोर्टिंग देशों/बैंकों की कुल अंतरराष्ट्रीय देयताओं और दावों का हिस्सा दिसंबर 2015 के अंत में क्रमशः 0.7 प्रतिशत और 0.3 प्रतिशत था।

कुल अंतरराष्ट्रीय देयताओं में एनआरई और एफसीएनआर (बैंक) जमाराशियों का हिस्सा पूरे वर्ष अपरिवर्तित रहा

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अगस्त 2013 में विशेष रियायती डालर स्वैप विंडो की घोषणा के फलस्वरूप एफसीएनआर (बैंक) जमाराशियों में दिसंबर 2013 में तीव्र उछाल पैदा होने के बाद उसका हिस्सा थोड़ा सा घट गया था और 2015 में

चार्ट 1 : भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और दावे-वार्षिक वृद्धि

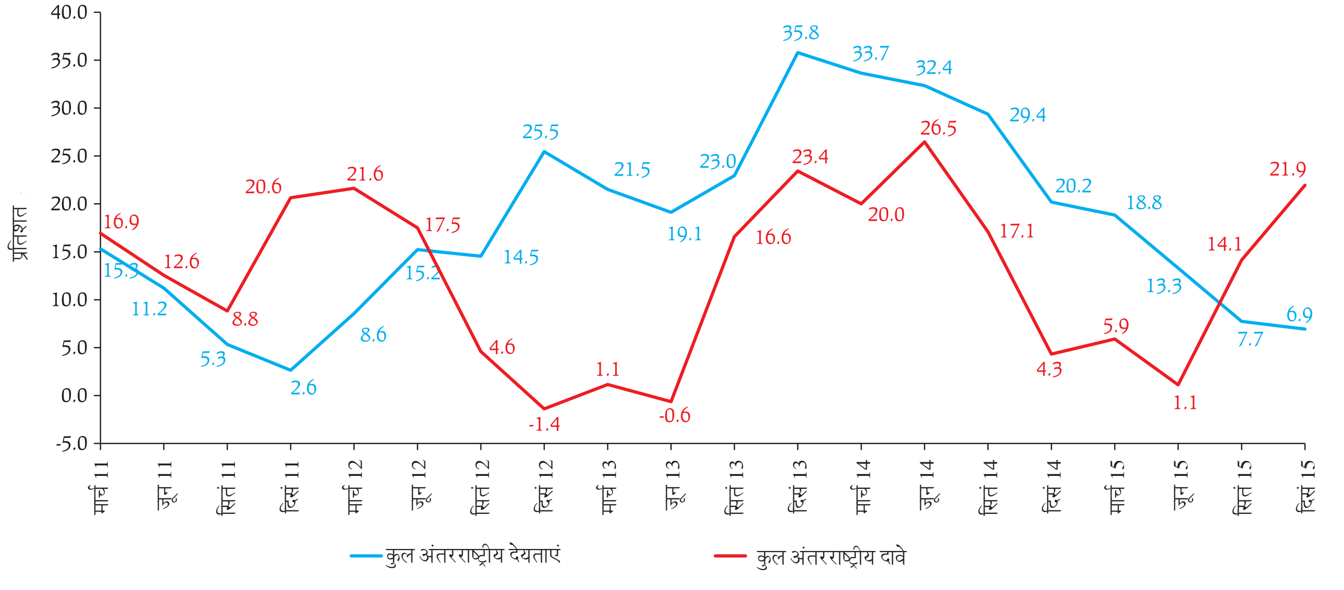

चार्ट 2 : अंतरराष्ट्रीय देयताओं के घटक

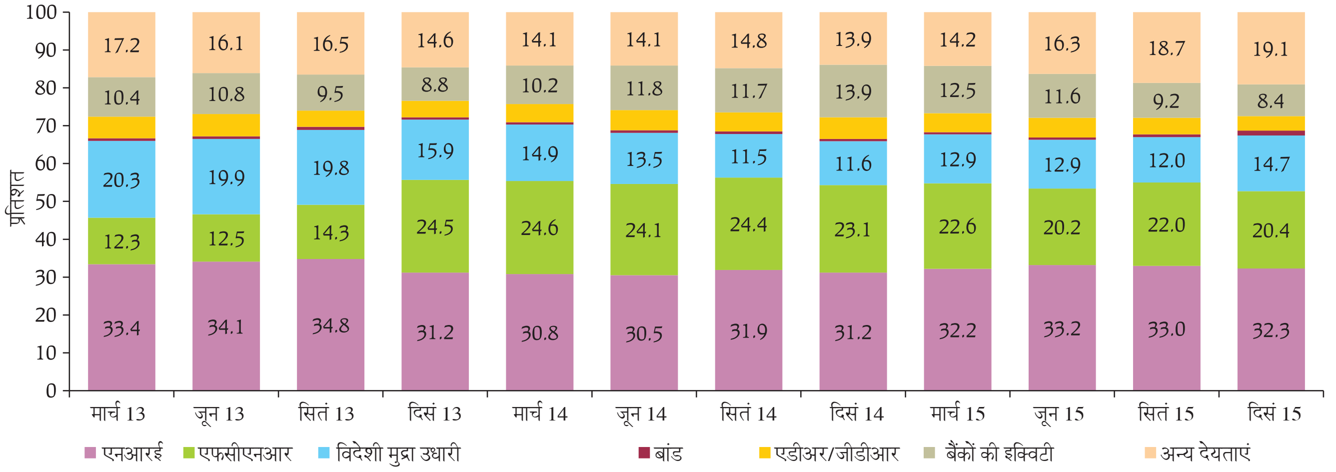

टिप्पणी : अन्य देयताओं में निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खातों की जमाराशियां, विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खातों की जमाराशियां शामिल हैं, अन्य विदेशी मुद्रा जमा (अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा जमा सहित), बास्ट्रो राशियां और एक्सचेंज गृहों में मीयादी जमा के रूप में राशियां, अनिवासी साधारण (एनआरओ) खाते, राजदूतावास खाते, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) खाते, एस्क्रो खाते की राशियां, फ्लोटिंग रेटनोट (एफआरएन) अन्य स्वामित्व वाले अंतरराष्ट्रीय ऋण प्रतिभूति निर्णय और भारत में विदेशी बैंकों की पूंजी/विप्रेषण योग्य लाभ तथा गैर-वर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय देयताएं।

समान बना रहा (चार्ट 2)। इसी तरह बकाया अनिवासी बाह्य (एनआरई) रुपए जमाराशियों का हिस्सा 2015 के दौरान लगभग समान बना रहा (चार्ट 2)।

5. कुल अंतरराष्ट्रीय देयताओं में बैंकों का विदेशी मुद्रा में उधार लेने का हिस्सा एक वर्ष पहले के 11.6 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2015 के अंत में 14.7 प्रतिशत हो गया था (चार्ट 2)।

अंतराष्ट्रीय दावों में 'अनिवासियों को प्रदत्त ऋण' के हिस्से में वृद्धि हुई है

6. अंतराष्ट्रीय दावों में 'अनिवासियों को प्रदत्त ऋण' का हिस्सा पिछले एक वर्ष की तुलना में दिसंबर 2015 के अंत तक बढ़ गया था (चार्ट 3)।

7. अंतराष्ट्रीय दावों के अंतर्गत 'निवासियों की प्रदत्त विदेशी मुद्रा ऋण' का हिस्सा वर्ष 2015 के दौरान तेजी से घट गया था और जो

चार्ट 3 : अंतरराष्ट्रीय दावों के घटक

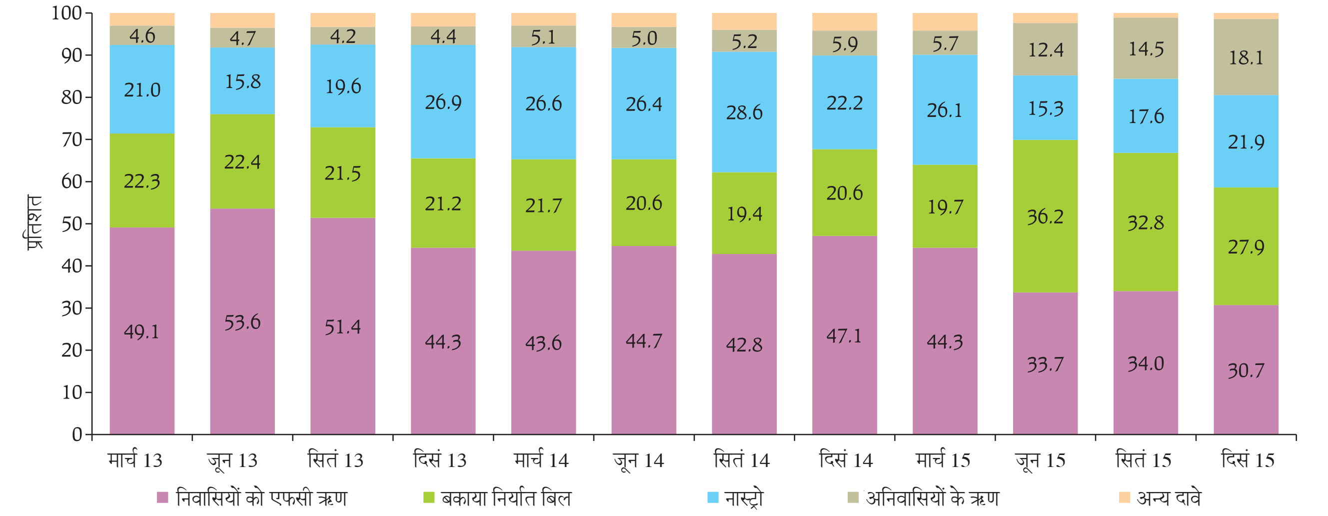

टिप्पणी : अन्य दावों में शामिल हैं, विदेशी मुद्रा/टीटी आदि जो हाथ में हैं, विदेश में इक्विटी में किए गए निवेश, भारतीय बैंकों की विदेश में स्थित शाखाओं को दी गई पूंजी और प्राप्त होने वाले लाभ तथा अन्य गैर-वर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय दावे

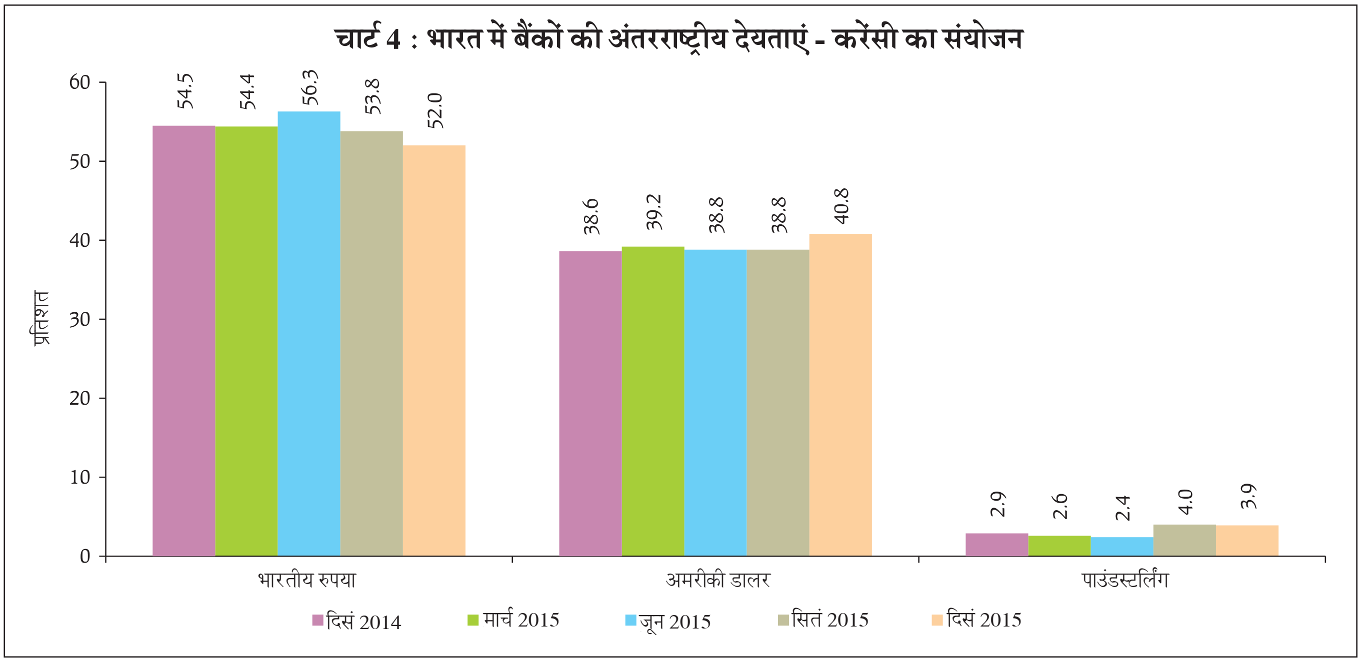

एक वर्ष पहले 47.1 प्रतिशत था वह घटकर दिसंबर 2015 में 30.7 प्रतिशत पर आ गया था (चार्ट 3)।

अंतरराष्ट्रीय देयताओं की कुल करेंसियों में अमरीकी डालर के हिस्से में मामूली वृद्धि हुई थी

8. अंतरराष्ट्रीय देयताओं की कुल करेंसियों में दिसंबर 2015 की तिमाही की समाप्ति से कमोबेश कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

9. अंतरराष्ट्रीय देयताओं में अमरीकी डालर का हिस्सा एक वर्ष पहले 38.6 प्रतिशत था जिसमें मामली सी वृद्धि हुई थी जो 40.8 प्रतिशत थी (चार्ट 4)।

10. अंतरराष्ट्रीय दावों के मामले में, अमरीकी डालर का वर्चस्व बना रहा, किंतु एक वर्ष पहले उसका हिस्सा 86.2 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2015 में 78.6 प्रतिशत हो गया था। अंतरराष्ट्रीय दावों में ₹ का हिस्सा एक वर्ष पूर्व की तुलना में दिसंबर 2015 में तुलनात्मक रूप से बढ़ गया था (चार्ट 5)।

अंतरराष्ट्रीय देयताओं और गैर-बैंक क्षेत्र के दावों में गिरावट पैदा हुई

11. गैर-बैंक क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय देयताओं की वृद्धि दिसंबर 2015 तक 0.7 प्रतिशत तक घट गई थी। अंतरराष्ट्रीय देयताओं में गैर-बैंक क्षेत्र के हिस्सा दिसंबर 2014 में 83.1 प्रतिशत था जो दिसंबर 2015 में घटकर 77.2 प्रतिशत हो गया (विवरण - 2 (₹) में डाटा निर्गत)।

12. लेकिन, गैर-बैंक क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय दावों में हिस्सा एक वर्ष पूर्व के 68.5 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2015 के अंत तक 71.6 प्रतिशत हो गया था। (विवरण - 2 (₹) में डाटा निर्गत)

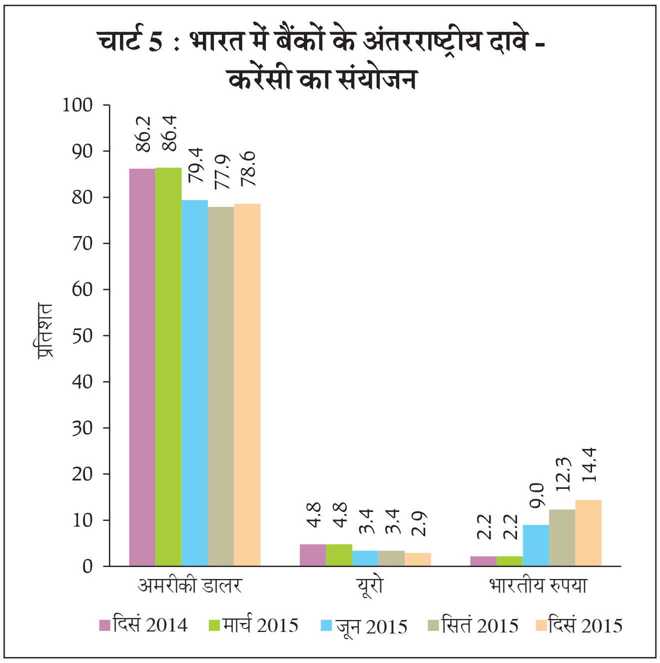

चार्ट 6 : लेनदेन करने वाली इकाइयों के निवासी देश के अनुसार भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं

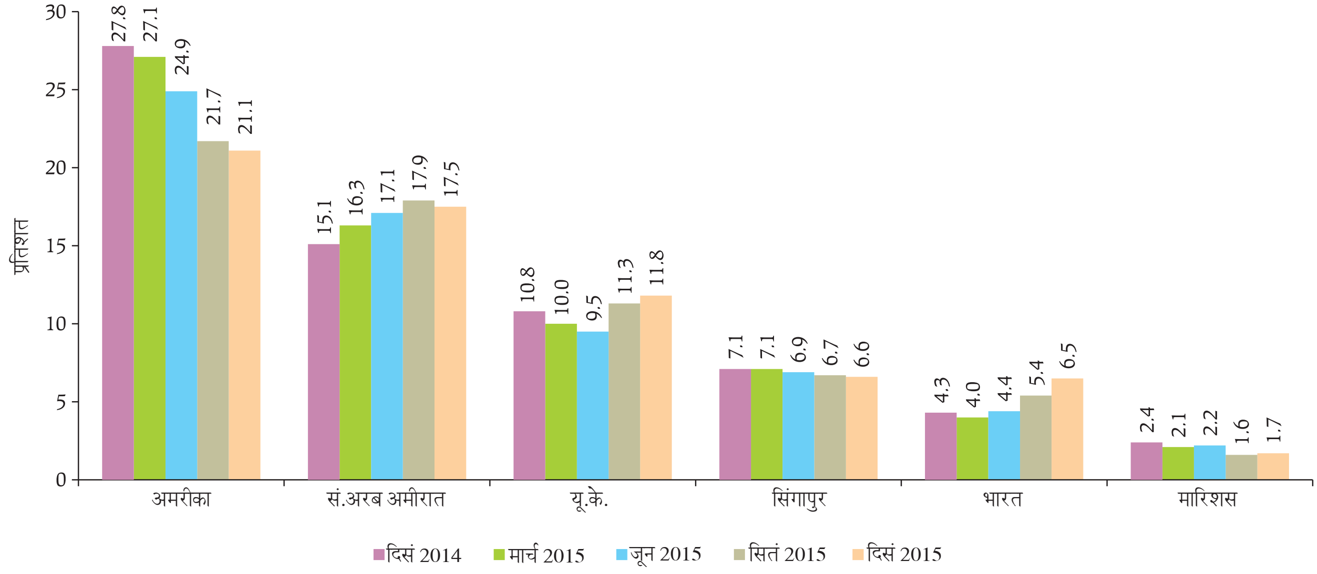

अमरीका के प्रति अंतरराष्ट्रीय देयताओं का हिस्सा घट गया है

13. वर्ष 2015 के दौरान अंतरराष्ट्रीय देयताओं में कुल गिरावट प्रमुख राष्ट्रों के संदर्भ में (चार्ट 6), विशेष रूप से अमरीका के प्रति हुई है।

भारत के संबंध में अंतरराष्ट्रीय दावों में गिरावट

14. भारत और अमरीका के संबंध में अंतरराष्ट्रीय दावों में गिरावट पाई गई जबकि हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध में वृद्धि दर्ज की गई है (चार्ट 7)।

चार्ट 7 : लेनदेन करने वाली इकाइयों के निवासी देश के अनुसार भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय दावे

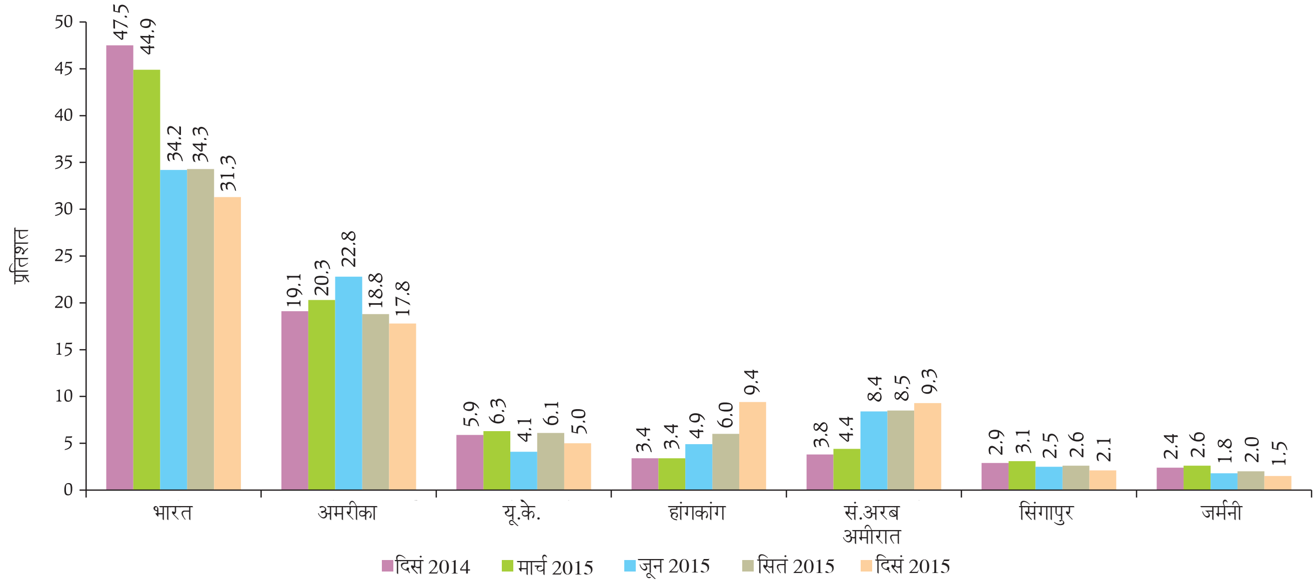

चार्ट 8: भारत से इतर देशों पर तत्काल राष्ट्रीय जोखिम आधार पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे

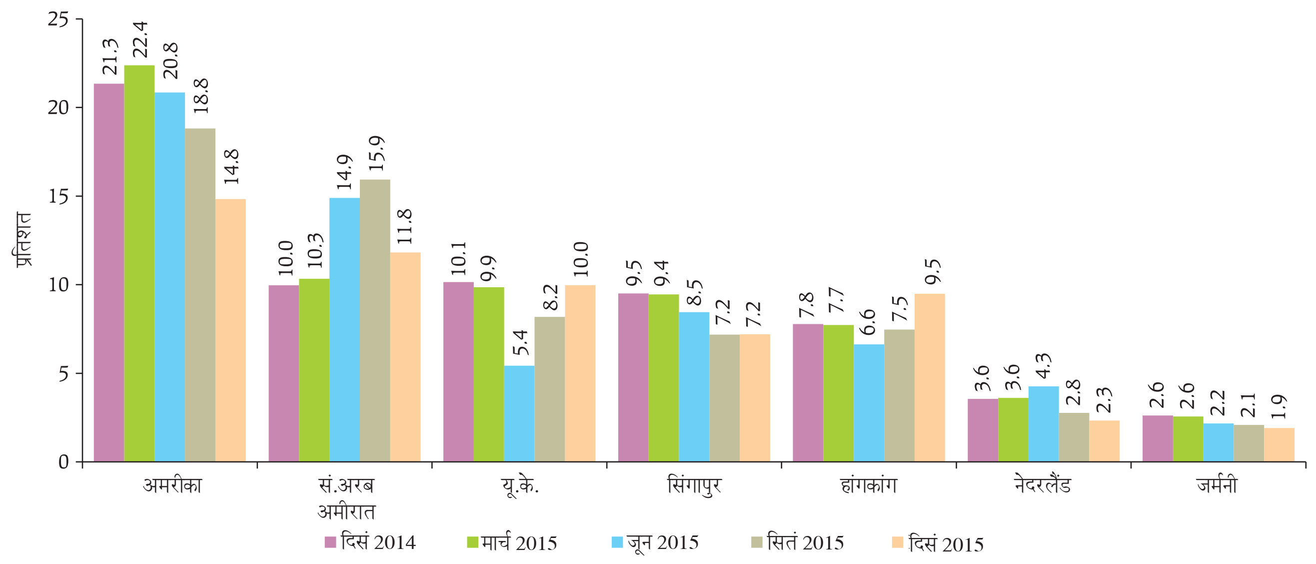

तत्काल जोखिम आधार पर अंतरराष्ट्रीय दावे[2] अपेक्षाकृत धीमी गति (सीबीएस पर आधारित) से बढ़े हैं

15. दिसंबर 2015 में अंतरराष्ट्रीय दावे हांगकांग के प्रति बढ़े है जबकि अमरीका, सिंगापुर और नेदरलैंड के प्रति पिछले वर्ष इसी अवधि की स्थिति की तुलना में घटी है (चार्ट 8)।

चुनिंदा राष्ट्रों के लिए अंतिम जोखिम आधार पर विदेशी दावे की राशि उच्च थी (सीबीएस पर आधारित)

16. अंतिम जोखिम आधार पर विदेशी दावे की राशि एक वर्ष पहले की ₹3,093 बिलियन की तुलना में दिसंबर 2015 में बढ़कर 4050 बिलियन रुपए हो गई थी (विवरण-10 (₹) में डाटा निर्गत)।

17. अंतिम जोखिम के आधार पर गारंटी तथा ऋण वचनबद्धता से उत्पन्न अनुषंगी दावे एक वर्ष पूर्व के क्रमशः 981 बिलियन रुपए तथा 167 बिलियन रुपए की तुलना में दिसंबर 2015 में 1272 बिलियन रुपए तथा 398 बिलियन रुपए पाए गए। लेकिन अंतिम जोखिम आधर पर डेरिवेटिव से उत्पन्न अनुषंगी जोखिम पिछले वर्ष की तुलना में दिसंबर 2015 में काफी बढ़कर 44.3 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ गया (विवरण-10 (₹) में डाटा निर्गम)। इस तीव्र परिवर्तन का कारण यह था कि कुछ बैंकों का डेरिवेटिव में एक्सपोजर बहुत अधिक था।

18. कुल अंतरराष्ट्रीय देयताओं में एशियान देश समूह की अंतरराष्ट्रीय देयताओं के हिस्से में वर्ष 2015 के दौरान हुई कमी में बहुत धीमी प्रवृत्ति पाई गई, जबकि उक्त समूह में कुल अंतरराष्ट्रीय दावों में उनका हिस्सा जून 2015 में उच्चतम 4.0 प्रतिशत तक पहुंच जाने के बाद दिसंबर 2015 में घटकर 2.9 प्रतिशत हो गया था (सारणी 2)।

19. कुल अंतरराष्ट्रीय देयताओं और कुल दावों में जी-10 देशों के हिस्से में वर्ष 2015 में मामूली गिरावट पाई थी (सारणी 2)।

20. भारत को छोड़कर सार्क देशों का अंतरराष्ट्रीय देयताओं में हिस्सा पिछले वर्ष के 0.2 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2015 में बढ़कर 0.4 प्रतिशत हो गया था, जबकि इन राष्ट्रों का अंतरराष्ट्रीय दावों में हिस्सा दिसंबर 2015 में घटकर 0.7 प्रतिशत हो गया था (सारणी 2)।

[2] अंतरराष्ट्रीय दावे (ए+बी) को इस प्रकार परिभाषित किया गया है - बैंक के सीमा-पर दावे (ए) तथा विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा विदेशी मुद्रा में स्थानीय दावे को मिलाकर (सी)। विदेशी दावे की परिभाषा इस प्रकार है - अंतरराष्ट्रीय दावां का जोड़े (ए+बी) और स्थानीय करेंसी में स्थानीय दावे (सी)।

सारणी 2 : विभिन्न देश के समूहों (भारत को छोड़कर) के बैंकों का भारत में अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर

(बिलियन रुपए में)

समूह	अंतरराष्ट्रीय देयताए									
	दिसं-14		मार्च-15		जून-15		सितं-15		दिसं-15	
सभी राष्ट्र	**10715.23**	**(100.0)**	**10925.45**	**(100.0)**	**10889.81**	**(100.0)**	**10561.07**	**(100.0)**	**11458.82**	**(100.0)**
एशियान	912.68	(8.5)	937.07	(8.6)	917.03	(8.4)	877.70	(8.3)	939.43	(8.2)
जी 10	4936.97	(46.1)	4850.39	(44.4)	4518.09	(41.5)	4192.18	(39.7)	4623.11	(40.3)
सार्क (भारत को छोड़कर)	20.54	(0.2)	23.37	(0.2)	18.12	(0.2)	23.03	(0.2)	43.42	(0.4)
पश्चिम एशिया	2398.68	(22.4)	2614.76	(23.9)	2888.73	(26.5)	2949.53	(27.9)	3006.72	(26.2)
ब्रिक्स (भारत को छोड़कर)	144.23	(1.3)	143.33	(1.3)	105.53	(1.0)	116.99	(1.1)	144.99	(1.3)
Groups	**अंतरराष्ट्रीय दावे**									
	दिसं-14		मार्च-15		जून-15		सितं-15		दिसं-15	
सभी राष्ट्र	**4125.70**	**(100.0)**	**4503.75**	**(100.0)**	**4251.08**	**(100.0)**	**4881.21**	**(100.0)**	**5030.92**	**(100.0)**
एशियान	134.74	(3.3)	161.30	(3.6)	171.73	(4.0)	183.11	(3.8)	146.25	(2.9)
जी 10	1324.84	(32.1)	1532.08	(34.0)	1438.05	(33.8)	1494.07	(30.6)	1386.51	(27.6)
सार्क (भारत को छोड़कर)	43.42	(1.1)	54.04	(1.2)	45.77	(1.1)	42.57	(0.9)	37.15	(0.7)
पश्चिम एशिया	252.95	(6.1)	287.48	(6.4)	468.15	(11.0)	575.27	(11.8)	594.47	(11.8)
ब्रिक्स (भारत को छोड़कर)	67.64	(1.6)	71.85	(1.6)	72.49	(1.7)	68.27	(1.4)	60.32	(1.2)

टिप्पणी: 1. ऊपर उल्लिखित समूह परस्पर रूप से पृथक नहीं।
2. एशियान समूह में शामिल हैं : सिंगापुर, बुनेई दारुस्सलाम, म्यानमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपीन, थाईलैंड और वियतनाम (एशियान समूह के अनुसार)।
3. जी. देशों में शामिल हैं : जापान, इटली, बेल्जियम, अमरीका, फ्रांस, यूंके, जर्मनी, कनाडा, नेदरलैंड, स्वेडन, स्विटजलैड (बीआईएस के अनुसार)।
4. सार्क देशों में शामिल है : पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भुटान, मालदीव, अफगानिस्तान।
5. पश्चिम एशिया में शामिल हैं : आज़रबाइजान, ईरान, अर्मिनिया, ओमन, यमन, लेबनान, सीरिया, ईराक़, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सउदी अरब (यूनिडो के अनुसार)।
6. ब्रिक्स देशों में शामिल हैं : ब्राज़ील, रुस, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
7. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रति प्रतिशत हिस्सा दर्शाता हैं।

21. पश्चिमी एशिया समूह ने वर्ष 2015 के दौरान संबंधित योग में दावों और देयताओं दोनों के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की है (सारणी 2)।

22. भारत में ब्रिक्स देशों (भारत को छोड़कर) के बैंकों के कुल अंतरराष्ट्रीय दावों में वर्ष 2015 के दौरान गिरावट हुई है।

अनुबंध I - आईबीएस के लिए सीजीएफएस का विस्तार

चरण I विस्तार विशेष रूप से एलबीएस के लिए है जिसमें निम्नलिखित परिवर्तन शामिल हैं :

- **पूर्ण वित्तीय तुलनपत्र :** एलबीएस का दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि रिपोर्टिंग बैंक के कुल वित्तीय दावे और देयताओं को शामिल किया जा सके, न कि केवल उनकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति। इसमें रिपोर्टिंग राष्ट्र के निवासियों के बारे में बैंक की स्थानीय करेंसी की स्थिति भी जुड़ जाएगी; यह एलबीएस/एन में विदेशी करेंसी ब्रेकडाउन का बेहतर परिष्करण होगा; और समस्त रिपोर्टिंग क्षेत्र के रिपोर्ट किए जाने वाले डाटा में और सुधार, संपूर्णता तथा स्थायित्व पैदा होगा।

- **प्रतिपक्ष-राष्ट्र संबंधी जानकारी :** एलबीएस/ एन में प्रतिपक्षी-राष्ट्र संबंधी आयाम जुड़ेगा। इससे एक साथ इन बातों को देखा जा सकेगा : (ए) रिपोर्टिंग संस्था की राष्ट्रीयता, (बी) रिपोर्टिंग संस्था का स्थान; और (सी) प्रतिपक्षों का स्थान (उदा. के लिए यू.के. में जर्मन बैंकों की जापान के प्रतिपक्षों के प्रति देयताएं)। वर्तमान में, एलबीएस/एन में केवल सीमा-पार के दावे एवं देयताएं बनाम अन्य समस्त राष्ट्रों में कुल प्रतिपक्षों के दावे एवं देयताएं।

चरण 2 का विस्तार एलबीएस तथा सीबीएस दोनों को प्रभावित करेगा और निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग गतिविधियों को बेहतर उपाय प्रदान करेगा :

- **राष्ट्र का ऋण संबंधी जोखिम :** सीबीएस में राष्ट्र के निवासियों के एक्सपोजर जहां रिपोर्टिंग बैंक का मुख्यालय स्थित है, और बैंक के कुल तुलनपत्र के आकार के लिए निरंतर उपाय जुड़ जाएंगे।

- **अंतरराष्ट्रीय बैंक ऋण :** सीबीएस और एलबीएस दोनों में बारीकी से प्रतिपक्ष क्षेत्र ब्रेकडाउन को लागू किया जा सकेगा इससे बैंकों की गैर-बैंक वित्तीय क्षेत्र पर निर्भरता तथा एक्सपोजर का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाना आसान होगा। इसकी सहायता से सीमा-पर ऋण-प्रवाह पर निगरानी रखने तथा राष्ट्र विशेष में ऋण में आई तेजी के डायनामिक्स को समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि ऐसी स्थितियां प्रायः अंतरराष्ट्रीय स्तर से ऋण प्रदान करके पैदा की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, एलबीएस/आर में डाटा घरेलू बैंक, विदेशी शाखाएं और विदेशी सहयोगी संस्थाओं के बीच अंतर कर सकेगा, जिससे यह विश्लेषण किया जा सकेगा कि इन बैंकों के तुलनपत्रों के प्रकार में किस प्रकार का अंतर है।

- **बैंक की निधि का पैटर्न :** बड़े-बड़े लिखतों जैसे-जमाराशि, अल्प एवं दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूतियां डेरिवेटिव्स, अन्य देयताओं एवं कुल इक्विटी द्वारा बैंक के निधीयन के ब्रेकडाउन को सीबीएस/आईआर में जोड़ा जा सकेगा। इन डाटा से यह मापा जा सकेगा कि बैंक की राष्ट्रीयता निधि के कम स्थिर संसाधनों जैसे - अल्पकालिक ऋण पर निर्भर हैं।

स्रोत : सीजीएफएस पेपर्स सं.47, बीआईएस अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी में सुधार - नवंबर 2012; बीआईएस

सारणी ए 1

बीआईएस अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी का सरलीकृत अवलोकन

2012 की दूसरी तिमाही से सूचित डाटा नीले रंग में (चरण 1) और 2013 की चौथी तिमाही से लाल रंग (चरण 2) में दिखाए गए

	स्थानवार बैंकिंग सांख्यिकी		समेकित बैंकिंग सांख्यिकी	
	निवासीवार (एलबीएस/आर)	**राष्ट्रीयतावार (एलबीएस/एन)**	**तत्कालजोखिमआधार (सीबीएस/आईआर)**	**अंतिम जोखिम आधार (सीबीएस/यूआर)**
रिपोर्टिंग राष्ट्र	44	43	31	24
रिपोर्ट किए गए कारोबार	वित्तीय आस्तियां और देयताएं (डेरिवेटिव सहित)		वित्तीय आस्तियां (डेरिवेटिव को छोड़कर), कुल आस्तियां और देयताएं (डेरिवेटिव सहित), पूंजी, जोखिम अंतरण	वित्तीय आस्तियां (डेरिवेटिव छोड़कर), अन्य अच्छे एक्सपोजर्स (डेरिवेटिव सहित)
रिपोर्ट किए गए ब्रेकडाउन बैंक प्रकार	समस्त रिपोर्टिंग बैंक, घरेलू बैंक, विदेशी सहयोगी संस्थाएं, विदेशी संस्थाएं, संघीय बैंक	अनुपलब्ध	समस्त रिपोर्टिंग बैंक, घरेलू बैंक, इन-साइड एरिया विदेशी बैंक[1] आउट-साइट एरिया विदेशी बैंक[2]	घेरलू बैंक
बैंक राष्ट्रीयता	अनुपलब्ध	≥43	≥31	≥24
स्थिति का प्रकार	सीमा-पार, स्थानीय		कुल, अंतरराष्ट्रीय (सीमा-पार और स्थानीय विदेशी मुद्रा में), स्थानीय एलसी	कुल, सीमा-पार, समस्त करेंसी में स्थानीय
करेंसी	स्थानीय, अमरीकी डालर, यूरो, येन, पाउंड, फ्रैंक, अन्य (वैकल्पिक)		एलसी पोजीशन में स्थानीय हेतु : > 160	अनुपलब्ध
परिपक्वता	देयताओं हेतु : ऋण प्रतिभूतियां (जिनमें से ≤ 1 वर्ष)		अंतरराष्ट्रीय दावा हेतु : ≤ 1 वर्ष, 1-2 वर्ष, >2 वर्ष	अनुपलब्ध
लिखत	ऋण और जमाराशि, ऋण प्रतिभूतियां, अन्य लिखत	*देयताओं हेतु :* ऋण प्रतिभूतियां	*आस्तियों हेतु :* दावे, कुल आस्तियां, जोखिम भारित आस्तियां *देयताओं हेतु :* जमा, ऋण प्रतिभूतियां (जिनमें से ≤ 1 वर्ष), डेरिवेटिव, अन्य देयताएं *पूंजी हेतु :* कुल इक्विटी, टियर 1 पूंजी	*अन्य महत्वपूर्ण एक्सपोजर्स के लिए :* डेरिवेटिव, ऋण वचनबद्धता दी गई गारंटी
प्रतिपक्ष राष्ट्र	> 200 (रिपोर्टिंग राष्ट्र सहित)	≥ 76 (रिपोर्टिंग राष्ट्र सहित)	> 200 (रिपोर्टिंग राष्ट्र सहित)	
प्रतिपक्ष क्षेत्र	बैंक[3] (जिनमें से : संबंधित कार्यालय, केंद्रीय बैंक) गैर बैंक[4], गैर-बैंक वित्तीय संस्थाएं, गैर-वित्तीय क्षेत्र (सामान्य सरकार, गैर-वित्तीय निगम, गृहस्थ)		सरकारी क्षेत्र (केंद्रीय बैंक सहित), बैंक (केंद्रीय बैंक को छोड़कर), गैर-बैंक निजी क्षेत्र, गैर-बैंक वित्तीय संस्थाएं, गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र (गैर-वित्तीय निगम, गृहस्थ)	

[1] इनसाइड एरिया के विदेशी बैंक जिनको उनके पूल बैंक द्वारा समेकन में नहीं लिया गया है उन्हें प्रोत्साहित किया गया है कि वे उसी प्रकार के ब्रेकडाउन को घरेलू बैंक के रूप में रिपोर्ट करें। [2] केवल अंतरराष्ट्रीय दावों के बारे में रिपोर्ट किया जाए। [3] 2013 की चौथी तिमाही से पूर्व, केवल एलबीएस/एन हेतु रिपोर्ट किया गया। [4] 2013 की चौथी तिमाही से पूर्व, केवल एलबीएस/आर हेतु रिपोर्ट किया गया।

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक; (2013) - बीआईएस अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी सूचित करने के लिए दिशानिर्देश : सीजीएफएस की संस्तुति के अनुसार चरण 1 और चरण 2 का विस्तार मार्च, पृ.2 सारणी ए 1.